**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 58**

**17.07.2017 को उत्‍तर के लिए**

**जलवायु परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन**

**58.** **श्री ए. विजयकुमार :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने देश में जलवायु परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन किया है;

(ख) क्‍या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्‍त राष्‍ट्र फ्रेमवर्क कन्‍वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का पक्षकार है। यूएनएफसीसीसी के अधीन सूचना देने संबंधी बाध्‍यता को पूरा करने के लिए भारत ने यूएनएफसीसीसी को प्रारंभिक राष्‍ट्रीय संप्रेषण (आईएनसी) 22 जून, 2004 को और दूसरी राष्‍ट्रीय संप्रेषण (आईएनसी) 4 मई, 2012 को प्रस्‍तुत की है।

 राष्‍ट्रीय संप्रेषणों के अतिरिक्‍त भारत को हर दो वर्ष में द्विवार्षिक अद्यतन सूचना (बीयूआर) यूएनएफसीसीसी को देनी होती है। भारत ने अपनी पहली द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 22 जनवरी, 2016 को भेजी। प्रथम द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्‍सर्जन 2010 में 2.136 बिलियन टन CO2 के बराबर थे। इसमें से, ऊर्जा क्षेत्र का अंशदान 71%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्‍पाद प्रयोग (आईपीपीयू) 8%, कृषि का 18% और अपशिष्‍ट क्षेत्र का 3% था। उत्‍सर्जनों का लगभग 12% वनों तथा फसली भूमियों के कार्बन सिंक एक्‍शन के द्वारा संतुलित कर दिया गया। अत: राष्‍ट्रीय जीएचजी निवल उत्‍सर्जन कुल मिलाकर 1.884 बिलियन टन Gg CO2 के बराबर हो गया द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार भारत का प्रति व्‍यक्ति GHG उत्‍सर्जन 2010 में 1.56 टन CO2 के बराबर था जो वैश्विक औसत और अन्‍य उभरती हुई अर्थ व्‍यवस्‍थाओं के औसत से काफी नीचे है।

(ख) और (ग) भारत ने जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। सरकार ने अपने लक्ष्‍यों की प्राप्ति तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जून 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यवाही योजना (एनएपीसीसी) आरंभ की है। एनएपीसीसी के अंतर्गत सौर ऊर्जा, संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता, वहनीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिप्रणालियों का रक्षण, हरित भारत, वहनीय कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान शामिल हैं। 32 राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों (यूटी) ने भी एनएपीसीसी के उद्देश्‍यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्‍य कार्यवाही योजना एसएपीसीसी तैयार की है।

स्‍वदेशी प्रयासों के परिणामस्‍वरूप भारत की जीडीपी की उत्‍सर्जन सघनता 2005 और 2010 के बीच 12% घट गयी है।

\*\*\*\*\*\*\*